

and uphold also the principles of democracy, especially Parliamentary democracy. I appreciate your concern. So are we concerned about it. Let us hope our concern is strong enough to resolve this impasse. Thank you.

Re. successful heart transplantation surgery by Dr. P. Venugopal and big team at AIIMS

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh); Madam, with your permission, I stand to compliment Dr. Venugopal and his team, who have been successful in doing transplantation surgery of a heart on a person, who was very seriously sick.

Madam, it is really a landmark surgery, in which India was lagging behind. It is a big success that the heart of a 35 year-old lady, after declaration of her brain-death, was removed and given to the donee. We are happy that the condition of the patient is stable and he is progressing well.

Madam, as you know, the first heart transplantation was done in the year 1967 in South Africa. Since then, our doctors were interested to do this sort of surgery. But due to certain lacunae in the definition of 'brain death' is defined not possible. Recently, a law was adopted in which 'brain death, is defined categorically. I congratulate the Government on bringing such a law enabling the doctors to perform this surgery. In our country, about 300 cases which require heart transplantation come up every year before doctors. I think a very good beginning has been made now. The most important aspect, perhaps, of the matter is that the cost of the operation, compared to that in the United States, is less. In the United States, the operation would cost \$ 100,000 to \$ 200,000 whereas in our country the cost of the operation has come to Rs. 40,000/- and the post-operative expenses will be about Rs. 40,000/-. That is, in Rs. 80,000/- this operation could be done.

Through you, Madam, I would like to send my congratulations to the team of doctors. I hope the patient will recover quickly and he will be able to work smoothly in future. I also hope that more milestones like this will be created by our doctors. Through you, Madam, I send my congratulations and compliments to the associates and whole team of Dr. Venugopal who have done this operation in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

Madam, I thank you very much for giving me this opportunity.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We all congratulate the team of doctors who performed this operation. We wish the recipient a complete recovery and a healthy life. We are happy that our scientists are not only doing research, but they have also been able to do, in India, all that the foreign countries do with much better equipment at their disposal. The whole House, I am sure, joins me.

There is one more thing. There is something one can always remember. That is, this gentleman will be carrying a woman's heart. I hope he will take care of it. They say men always carry women's heart. I do not know where. But here, he will be carrying the woman's heart in the true sense of it.

SPECIAL MENTIONS

Need to check growing vulgarity and violence in films

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) :
उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक ऐसे मामले की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसने पूरे देश में और पूरे समाज में एक चारित्रिक संकट की स्थिति पैदा कर दी है और यह समस्या हिन्दुस्तान की फिल्मों में बढ़ रही अश्लीलता और हिंसा की प्रवृत्ति का है। स्थिति अब ऐसी

हो गई है कि पहले तो जब हम यह टी.वी. घरों में नहीं हुआ करते थे, टॉकीज या थियेटर्स में लोग फिल्म देखने जाते थे तो कुछ लोगों को यह मालूम पड़ जाता था कि यह फिल्म कैसी है। इसको बच्चों के साथ देखा जा सकता है या नहीं और उनसे बचा जा सकता है। लेकिन टेलीविजन जो हमारे बेडरूम तक पहुंच गया है इसमें ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी, जिसमें जरा भी लज्जा और शील है, वह परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर फिल्मों को नहीं देख सकता। हिंसा के ऐसे नए-नए तरीके फिल्मों के जरिए लोगों के सामने आ रहे हैं कि चाहे जलगांव सैक्स स्कैंडल जैसी बातें हों, चाहे दिल्ली में बच्चों के अपहरण जैसी बातें हों, इन सब का खोव किस तरह से कार्य हों, यह फिल्मों के जरिए लोगों के सामने आ रहे हैं। इस तरह लोग अपराधों में संलग्न होते हैं और उसी तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। महोदया, मुझे नहीं मालूम कि फिल्म सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पुत्र और पुत्रियां हैं या नहीं, लेकिन उनके माता-पिता जरूर होंगे यह मैं निश्चित तौर पर मानता हूं और यह लोग इस तरह की फिल्मों पास कर देते हैं, यह बहुत ही चिंता का विषय है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से मांग करना चाहूंगा कि फिल्म सेंसर बोर्ड से इन लोगों को तो तत्काल हटाया जाए जोकि फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। जो फिल्में बनाते भी हैं और पास भी करते हैं। महोदया, जो चीजें करती हो उसी को अगर न्याय करने की इजाजत दे दी जाएगी तो वह किसको ढूँढ देंगे? कभी-कभी तो लोग कहते हैं कि अगर टी.वी. सेशन ही फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हों तो कुछ सुधार हो सकता है। दूसरे मैं चाहूंगा कि इस फिल्म इंडस्ट्री को जहाँ से कि ये फिल्में बनकर आती हैं, उसे भी कंजुमर्स प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में लाया जाए ताकि जो इससे पीड़ित हो या जिसकी मेंटीमेंट इजोर्ड हों, वह उसमें जा सके और न्याय पा सके। महोदया, आर्नोल्ड टायनबी

एक जगह लिखा कि दुनिया की तमाम सभ्यतयें इसीलिए नष्ट हो गयीं और उनमें दो चीजें बची अन्धोहलज्ज और न्यूडिटी। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि इन फिल्मों के जरिए ये दोनों चीजें हिन्दुस्तान में बढ़ रही हैं जोकि देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस संबंध में जरूर कार्यवाही हो। अब हम लोग केवल न्यूज सुनने के लिए तो टी.वी. खोल सकते हैं, लेकिन बच्चे बैठे हों तो कोई कार्यक्रम नहीं देख सकते। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. It is a very serious matter and I am sure, somebody from the Government, will take note of it, Mr. Mu-kherjee, a very senior Minister, from the Government side is there. Some more Ministers are there. Smt. Margaret Alva is there They should convey to the Government the feelings of the Members.

श्रीमती बीना वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपासनापति महोदय, माननीय यादव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि फिल्मों में बढ़ती हिंसा और नग्नता को रोका जाना चाहिए। यह हमारे समाज में बल्लैरिटी तो फैलाती ही है, लेकिन इससे आपराधिक मनोरंजन की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर अवश्य चैक लगाया जाना चाहिए। मैडम, कुछ समय पूर्व हमारे सूचना प्रसारण मंत्रीजी ने एक सभा में कहा था कि इस विषय को कंजुमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा। तो सरकार इस पर जल्द विचार करे कि किस तरह से "बल्लैरिटी एंड क्रिमिनलायजेशन इन फिल्म्स" और उनकी थीम्स का जो अपराधीकरण हो गया है और अपराध पर आधारित जो फिल्म बनती हैं, उन पर चैक लगाया जाए। साथ ही खास तौर से ऐसे गाने और डांसेस जिनमें कि बल्लैरिटी का एक पूरा उदाहरण होता है नमूना होता है उस पर भी चैक लगाया जाए। इस तरह

के गाने और डासेस या पॉटकुलर सौन को कज्मर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदया कुछ समय पूर्व मद्रास हाय-कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उसमें विजय शंकर नामक अपराधी को फांसी की सजा दी गयी थी। उसने छः हत्याएँ एक साथ की थीं लेकिन उसने कोर्ट में अपनी बयान देने हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न समाज के सामने रखा था कि मैं अकेला ही इन हत्याओं का जिम्मेदार नहीं हूँ। उसने एक फिल्म का नाम दिया था और बताया था कि मुझे हत्या करने की प्रेरणा उस फिल्म को देखकर हुई थी। तो क्या ऐसी फिल्मों से जुड़े प्रोड्यूसर्स एक्टर्स और डायरेक्टर्स को कज्मर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है क्योंकि वह भी इस सबके लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार है। इस संबंध में भी विचार होना चाहिए।

महोदया तीसरी बात में मुझसे के तौर पर यह कहना चाहेंगी कि मनोरंजन चैनल खान तौर से मैट्रो चैनल जोकि मनोरंजन चैनल है उसको "वे चैनल" बनाने पर विचार किया जाना चाहिए जिससे कि इस तरह की बढ़ती हिंसा नग्नता के नाम पर जो चीप मनोरंजन हम मैट्रो चैनल के नाम से दे रहे हैं उसे भी "वे चैनल" बना दिया जाए ताकि जिसकी प्राथमिकता हो वह उसे ले अन्यथा न ले। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्रीमती बीणा बर्मा : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैडम मैं चाहूँगी कि आपकी तरफ से भी कुछ डायरेक्टिव सरकार को जायें ताकि इस पर कुछ न कुछ चैक हो सके।

उपसभापति : आप ठीक कह रही हैं कि सरकार ऐसे खर्च न करके इस तरह की गोजे एक्सचेजर्स का पैसा होता है यह एक्सपेंस भीड़िया है टेलीविजन तो मैट्रो चैनल पर मैं तो इसे देखती नहीं हूँ सलिए मुझे मालूम नहीं कि कौनसे चैनल रा आता है अगर मैट्रो चैनल पर यह आ रहा है और सरकार टैक्स-पेयर्स की मनी

से लोगों को बतगेरिटि दिखा रही है और इसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसको ऐसे देकर बतगेरिटि देखना हो वह अपना जाने उनकी अपनी मर्जी है।...

श्रीमती बीणा बर्मा : सिनेमा में जाते हैं लोग उसे देखकर।

उपसभापति : और प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस बात के ऊपर कहा था मीटिंग उन्होंने बुलाई थीमैंने पढ़ा था। मैं समझती भिनिस्टर्स की जो के सबसे ऊँचे स्तर पर हैं कि इस देश का इजहार दुप्रा है इसके ऊपर चिंता कि जब प्रधान मंत्री और मुझे यकीन है के ऊपर गौर कर जो खुद इस बात कुछ न कुछ नतीजा रहे हैं तो जरूर निकलेगा।

SHRI ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala); Madam, I also want to speak on this matter

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please speak.

SHRI ABDUSSAMAD SAMADANI: Madam, this is a very serious problem that is brought to your notice. My humble suggestion at this juncture is that some arrangement must be made to educate the Censor Board people about the concept of art in administering things. I think, the real problem is lack of knowledge about the concept of art. Many people think that art is something vulgar. They are separating art from life. There, some education has to be given to these people. I am reminded of a couplet of Allama Iqbal:

ए अहले नजर जोके नजर खव है लेकिन,
जो जै की हकीकत को न देखे वह नजर
क्या ?

मकसुदे हुनर भोजे हमाने से अबदी है,
ये इक नफस दो नफस, मिसले शरर क्या?
बे भोजजा दुनिया में उभरती नहीं कौमें,
जो जाबेकतीमी नहीं रखती, वह नजर क्या ?

Real art is something revealing the realities of life. I do not know what

her our Censor Board people, our television people are concerned about all these things. I request the Chair that some arrangement be made to educate the people about the concept of art. Thank you, Madam.

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : इस मसले को कन्ज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाया जा सकता है या नहीं, इस मसले को हम देखेंगे। मैं हाउस के सामने इतना ही कह सकता हूँ कि यह बहुत ब्रह्म बात हाउस के सामने आई है, इसको हम जरूर गंजामिन करवायेंगे और जो कुछ इसमें हो सकता है करने की कोशिश की जाएगी।

उपसमापति : शुक्रिया। यह सब लोगों का मंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने रिएक्ट किया। हो सकता है कि मसले की ग्रहमियत को, उसकी गंभीरता को देखकर और उसके साथ साथ आपकी शेर-ओ-शायरी जी थी उसने वास्तव में हमारे जमीर को झंझोर दिया और मंत्री जी भी बोले कि ठीक बात है। अच्छी।

Art can be beautiful. Art should be beautiful. Art is not vulgar. Hum-our is not vulgar. But it is how people project it, how people depict it which is important. We do not have to show something vulgar to enjoy and it should not be through violence, violence on women or children, because what they show is violence, generally on children. We have seen everyday in the House Members expressing concern about abduction of children in Delhi. The people have imbibed this vulgarity and violence through this very strong medium.

Thank you, Mantriji. for giving your comments.

Shri Hariprasad.

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra); Madam, there is no quorum in

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is it?

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): There is nothing... (*Interruptions*) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hariprasad, your name is given. I will call you.

SHRI SATISH PRADHAN; Madam, what about quorum?

SHRI B. K. HARIPRASAD: It is quite okay, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot say okay. It is for the Chair to decide that. When a Member raises the issue of quorum, I have to decide whether there is quorum or not.

SHRI B. K. HARIPRASAD: He is not serious. He is taking it back.

THE DEPUTY CHAIRMAN; It is not a question of statistics. Let us find out if there is quorum or not.

SHRI B. K. HARIPRASAD: Madam, I would like to draw the attention of the Government....

THE DEPUTY CHAIRMAN: We can-not function until there is quorum. Please sit down. Let there be quorum. What Mr. Pradhan has raised is a technical point. We are thankful to him because, after all, the House should be run in order. The House should not be run in disorder. When the Members stand up and obstruct the running of the House we say, "The House is not in order." When there are not enough Members, if a Member shakes the conscience of the Members who are not here then we have to listen to him.

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh); Madam, I stand on a point of order. This question is raised off and on. The whole Opposition has boycotted the House. A major chunk of the Members is not attending the House. In such a situation, Is it necessary to consider

the question of quorum?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The responsibility of quorum is on the Government. It is not on the Opposition.

SYED SIBTEY RAZI: It is all right. But we want your ruling.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sibtey Razi, I think my calculation is correct. The Congress Party Members are more than 25.

SHRI P. UPENDRA: Madam, the rule is very clear. You cannot change the quorum every time. whether some people boycott the House or not, the quorum remains the same.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The responsibility of quorum is on the Government. I mean the ruling party. The ruling party has brought the quorum. So, there is no problem now. But we cannot change it because two Members are less. It is never done.

श्री ईश बल्ल यादव (उत्तर प्रदेश) :
मैडम, सरकार को और कांग्रेस को चिंता नहीं है, एकमात्र सदस्य सतीश प्रधान जी, शिव सेना के हैं, उन्होंने यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है इसलिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ ।

उपसभापति : इसका भी धन्यवाद कि वह खुद बैठकर कोरम पूरा कर रहे हैं ।

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): The Opposition is not entering the House. But they are signing the register outside and they are claiming daily allowance.

THE DEPUTY CHAIRMAN: They are not. I cannot give any ruling on what is happening outside the House. I am not responsible for what is happening in the lobby.

SHRI SURESH KALMADI: But they

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) :
मैडम, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई नहीं कर रहा है कि बायकाट कर रहे हैं, कलमाडी जी को गलत जानकारी मिली है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is something else. Mr. Hariprasad, finally you speak.

Need to check hoarding and profiteering In coffee

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Madam, I would like to draw the attention of the Government to hoarding and profiteering, which has resulted in the steep hike in coffee prices, in coffee. The liberalisation of pooling system, which has left the domestic coffee market at the mercy of the market forces, has turned this cheerful drink bitter to swallow. Against an estimated crop of 2.25 lakh tonnes a year, the domestic consumption of coffee is estimated at 70,000 tonnes. Yet the coffee prices have shot up steeply in recent months. This is affecting very badly the middle class in the southern part of the country. The Coffee Board says that the price rise is due to the hike in the auction price in the last quarter owing to a shortfall in production. As far as the consumer is concerned, the recent policy change which is initiated, is a mockery. In the past the Board had to act as a saviour of the growers' lobby to safeguard their interest from the sluggish demand. Now it seems that the Board has to reverse its role by coming to the rescue of the consumers from the lobby of coffee-growers. It would be wrong to say that the growers have benefited from this situation as a substantial portion of the auction stock has been cornered by the exporters and the traders expecting a big demand in the export market. In the name of export earning the coffee trade has exploited the domestic market. The havoc caused by the market forces has been compounded further by big players buying of stocks in auction at high prices for the export market. the market intervention